<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फ. सं. 6/60/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
4 वीं मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 31 दिसंबर, 2025

<u>मामला सं. - एडी (ओआई) – 52/2025</u>

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

विषय: चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "नायलॉन 6 चिप्स और 3 से कम सापेक्ष चिपचिपाहट (आरवी) के साथ कणिकाओं के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत।

1. **फ. सं. 6/60/2025-डीजीटीआर:** समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (क्षति के निर्धारण के लिए डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया था (इसके बाद "नियम" या "एंटी-डंपिंग नियम" के रूप में संदर्भित), मैसर्स गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी जाना जाता है) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी " के रूप में संदर्भित) के समक्ष "नायलॉन 6 चिप्स और दानेदार पदार्थ जिनकी सापेक्ष श्यानता (आरवी) 3 से कम है" (जिसे आगे "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित डंपिंग-विरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो चीन गणराज्य और रूस (जिसे आगे "विषय देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यात किए जाते हैं।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषय देश से संबंधित वस्तुओं के डंप किए गए आयात से भौतिक क्षति हो रही है और उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान अनुप्रयोग में विचाराधीन उत्पाद *नायलॉन 6 (पॉलियामाइड 6) चिप्स और कणिकाओं के साथ सापेक्ष चिपचिपाहट (आरवी) 3 से नीचे है।*

4. विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल उद्योगों जैसे हल्के-ड्यूटी गैर-कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए भी उपयुक्त हो सकता है।

<u>बहिष्करण</u>

5. पाउडर के रूप में उत्पाद को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

<u>माप की इकाई</u>

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (किलोग्राम) है।

<u>टैरिफ वर्गीकरण</u>

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत उप-शीर्षक 3908 10 11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, आवेदक ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोड 3908 10 19, 3908 10 21, 3908 10 39, 3908 10 41, 3908 10 49, 3908 10 79 और 3908 90 00 के तहत भी आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की गई वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित लेख और जो विषय देश से आयात किया गया है, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। विषय सामान और आवेदक द्वारा निर्मित लेख तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता विषय वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को *प्रथम दृष्टया* विषय देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वस्तु के समान माना जाता है।

ग. विषय देश

10. वर्तमान जांच में विषय देश **चीन पीआर** और **रूस है।**

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 (12 महीने) तक की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में माना है (इसके बाद " पीओआई " के रूप में संदर्भित)। क्षति की जांच अवधि पिछले तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई को कवर करेगी।

ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

12. यह आवेदन मेसर्स गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने संबंधित देशों से उक्त वस्तुओं का आयात नहीं किया है और संबंधित देशों के उत्पादकों या निर्यातकों से उनका कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वे एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का 100% हिस्सा उन्हीं का है। अतः, आवेदक प्रथम दृष्टया एडीडी नियम, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की श्रेणी में आता है और आवेदन एडीडी नियम, 1995 के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. चीन के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक । के नियम-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8(2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8(3) के अनुसार विषय वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर के लिए, सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, आवेदक को बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या लागत के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए,

आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें मार्जिन के लिए उचित वृद्धि की गई है।

ख. रूस के लिए सामान्य मान

15. आवेदक ने दावा किया है कि रूस में तुलनीय घरेलू कीमतें ऐसी जानकारी की गोपनीय प्रकृति के कारण उपलब्ध नहीं थीं; इसलिए, कैप्रोलैक्टम के निर्यात-आधारित मूल्यों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विद्युत शुल्कों, अनुमानित विनिर्माण और रूपांतरण लागत, बिक्री के लिए उपयुक्त परिवर्धन, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ सहित यथोचित रूप से उपलब्ध सूचना का उपयोग करके उत्पादन की लागत का निर्माण करके वैकल्पिक आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था।

16. हालांकि, प्राधिकारी ने आरंभ करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसका निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा दोनों विषय देशों के लाभ के लिए उचित अतिरिक्त राशि शामिल है।

ग. निर्यात मूल्य

17. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम डेटा में दी गई सूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय आदि के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

घ. डंपिंग मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-पूर्व स्तर पर की गई है, जो प्रथम *दृष्टया* यह दर्शाता है कि पाटन माजन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देशों से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* इस बात के प्रमाण हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है।

ङ. <u>क्षति और कारण लिंक</u>

19. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देश से विषय आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों शब्दों में वृद्धि हुई है। आयात के कारण मूल्य में कमी और मंदी के प्रमाण हैं। विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

20. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति

के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमों के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच आरंभ करने, कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए उचित हैं, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

च. <u>डंपिंग रोधी जांच की शुरुआत</u>

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और विषय देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के कथित डंपिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और डंप किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, विषय देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

छ. <u>प्रक्रिया</u>

22. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

छ. <u>जानकारी प्रस्तुत करना</u>

23. सभी इच्छुक पक्षों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए सभी संचार और प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियाँ का विवरण खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जिन्हें विचाराधीन उत्पाद से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू

व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण कर सकता है, जैसा कि ऊपर पैरा (23) में उल्लिखित है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को इसका गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पार्टियों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर (https://www.dgtr.gov.in/) की वेबसाइट पर जाएं ताकि वे विषय की जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

ज. <u>अंतिम तिथि</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक सबमिशन के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) को संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या एडी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा, 1995. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए 15 दिन की अवधि इस दीक्षा अधिसूचना के ऊपर पैरा 28 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था या दीक्षा अधिसूचना से अलग है, तो समय का विस्तार 15 दिनों तक बढ़ाया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित

समय का 15 दिन का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। 15-दिन के विस्तार (यदि दी गई हो) से परे समय के और विस्तार के अनुरोधों पर आमतौर पर असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा, एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप।

32. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से ऊपर पैराग्राफ 28 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद सबमिट किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

झ. <u>गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना</u>

33. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत हो सकती हैं।

34. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

35. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

36. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जो ऐसी जानकारी के आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां इंडेक्सेशन संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो उस जानकारी पर निर्भर करती है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-

गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान जिसमें इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

38. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

40. इसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी सबमिशन, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ञ. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

41. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ट. <u>असहयोग</u>

42. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
नामित प्राधिकारी